विनोद एस. भारद्वाज से पहले, जे.

प्रोविडेंट फंड इंस्पेक्टर-याचिकाकर्ता

बनाम

मैसर्स बैप्टिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल-प्रतिवादी

2021 का सी. आर. एम.-एम **No.7892**

14 मार्च, 2022

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, **1952-S.S. 6,**धारा**14 (1-**ए) और **14-**ए-सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, **1860-**अभियुक्तों का निर्वहन-अभियुक्तों के खिलाफ आरोप- **प्रत्येक महीने के लिए** प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन कोष में नियोक्ता के **अंशदान** का भुगतान **उस महीने के अंत में** 15 **दिन के भीतर** करने में विफलता-आयोजित, एक बार जब शिकायतकर्ता व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का विकल्प चुनता है, तो प्रथमदृष्टया यह स्थापित करने का बोझ **होता है** कि उन व्यक्तियों पर कानूनी इकाई **के चूक** के कृत्यों के लिए **जिन व्यक्तियों पर** मुकदमा चलाया जाना है, वे **ऐसे** व्यक्ति हैं जो **इसके लिए जिम्मेवार है।** कानूनी इकाई के प्रबंधन और मामलों के नियंत्रण में हैं जिन पर मुकदमा **चलाये जाने की मांग की गई है। यह** दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि आरोपी व्यक्ति प्रतिवादी के पदाधिकारी थे-शिकायतकर्ता पर बोझ जो उत्तरदाताओं पर मुकदमा चलाना चाहते हैं - **केवल अगर पर्याप्त सामग्री है जो उस व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष निकाल सकती है जिस पर मुकद्मा चलाये जाने की मांग की गई है वह स्थापना के मामलों का प्रभारी है, मुकद्मा चलाने की**

मांग व्यक्ति पर इसका भार सीनांतरित हो जायेगा। आरोपी का उचित निर्वहन माना गया है कि यह अच्छी तरह से तय स्थापित किया गया है कि आपराधिक अभियोजन का किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है और इस तरह की स्वतंत्रता को शिकायतकर्ता की इच्छा पर कम नहीं किया जा सकता है।एक बार जब कोई शिकायतकर्ता किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का विकल्प चुनता है, तो प्रथमदृष्टया यह स्थापित करने का बोझ उस पर पड़ता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किसी न्यायिक संस्था की चूक के कृत्यों के लिए मुकदमा चलाने के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया है वे ऐसे व्यक्ति है जो इसके लिए जिम्मेवार हैं अंतिम नियंत्रण में है न्यायिक ईकाई के प्रबन्धन और मामलों पर मुकद्मा चलाने की मांग की गई है हालाँकि, याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता यह स्थापित करने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है कि कैसे प्रतिवादी-अभियुक्तों का मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मामलों पर अंतिम नियंत्रण कैसे हैं। जब तक कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अर्थ के तहत उत्तर भारत के बैपरिस्ट सीनियर सैकेडरी स्कूल को नियोक्ता नहीं माना जाता है, तब तक उत्तर भारत के बैपटिस्ट संघ के पदाधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, 2003 के अर्थ के तहत 'नियोक्ता' उस स्कूल का प्राचार्य होता है जिसे आरोपी के रूप में भी शामिल नहीं किया गया है।

एक प्रोविडेंट फंड इंस्पैक्टर बनाम एम/एस बैप्टिस्ट सीनियर

617

माध्यमिक विद्यालय (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

परिसर का मालिक उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का नियोक्ता नहीं होगा। शिकायतकर्ता द्वारा यह स्थापित किया जाना चाहिए कि परिसर का मालिक उस प्रतिष्ठान के मामलों को भी नियंत्रित करता है जिसके खिलाफ चूक का आरोप लगाया गया है।उक्त भार को मुख्य रूप से शिकायतकर्ता द्वारा उतारा जाना चाहिए जो प्रतिवादी पर

मुकदमा चला रहा है और केवल अगर पर्याप्त सामग्री है जो इस निष्कर्ष पर ले जा सकती है कि जिस व्यक्ति पर मुकदमा चजाए जाने की मांग की गई है वह प्रतिष्ठान के मामलों का प्रभारी है, तो क्या भार उस व्यक्ति पर स्थानांतरित होगा जिस पर मुकदमा चलाया जाना चाहता है।यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के मामले में उपरोक्त कमियों को देखा और इसलिए उत्तरदाताओं को बरी करने के लिए धारा 245 Cr.P.C के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। मैं पाता हूँ कि विवादित आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है और यह रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की किसी भी गैर-प्रशंसा से भी पीड़ित नहीं है।

(पैरा 15)

सुमित गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता

मनोज बजाज, अधिवक्ता,

याचिकाकर्ता के लिए।

विनोद एस. भारद्वाज, जे. (मौखिक)

(1) यह मामला कोविड-19 महामारी की स्थिति के आलोक में और निर्देशों के अनुसार वेबेक्स सुविधा के द्वारा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा से उठाया गया है।

(2) तत्काल याचिका में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध की खंड 6,14 (1-ए) और 14-ए के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिवानी द्वारा आपराधिक शिकायत No.29/14 दिनांक 08.08.2014 में पारित दिनांक 06.02.2018 (अनुलग्नक पी-1) के आदेश को चुनौती दी गई है।प्रावधान अधिनियम, 1952 का शीर्षक "भविष्य निधि निरीक्षक बनाम मेसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अन्य, जिसके तहत अभियुक्तों को आरोपमुक्त कर दिया गया है।

(3) तत्काल याचिका दायर करने के लिए तथ्यों के संक्षिप्त संदर्भ से पता चलता है कि कर्मचारी भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध धाराओं की धारा 6,14 (1-ए) और 14ए के साथ पठित कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।प्रावधान अधिनियम, 1952।उक्त शिकायत में किए गए प्रासंगिक अभिकथन निम्नानुसार निकाले गए हैं:

"2. मेसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्कुलर रोड, भिवानी (इसके बाद उक्त प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) है।

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध के अंतर्गत आने वाला एक प्रतिष्ठान।प्रावधान अधिनियम, 1952 (इसमें बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित)।इसे कोड No.HR/2554 आवंटित किया गया है।

3. **यह** कि आरोपी नंबर 1 एम/एस बैपटिस्ट सीनियर स्कूल का प्रतिनिधित्व रेव सोलोमन डेविड, 2 रेव सोलोमन डेविड, प्रबंधक, बीयूएनआई प्रबंधक, 3 दयाल मसीह, अध्यक्ष, **बी.यू.एन.आई**,4. डैनियल **बुद्ध** मसीह, सचिव-खजांची,5. जॉय एस. सिंह, बी. सी. टी. ए.6. एस. के. राज, सदस्य बी. यू. एन. आई., उक्त प्रतिष्ठान के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभारी हैं।उन्हें उक्त प्रतिष्ठान के संबंध में उक्त अधिनियम, योजना (पेंशन योजना या बीमा योजना) के सभी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।

4. **यह** कि कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैराग्राफ 4 के तहत, अभियुक्तों को उस महीने की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रत्येक महीने के लिए उक्त प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन कोष में नियोक्ता के योगदान का भुगतान करना आवश्यक है।

5. कि कई अनुरोधों के बावजूद, अभियुक्त शिकायत के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित तरीके से भुगतान करने में विफल रहा, निम्नलिखित अवधि के लिए पेंशन निधि योगदानः-

महीना	पेंशन संबद्धता की मात्रा
2/2011	16702
3/2011	16702
4/2011	16713
कुल	50117

6. **मैं प्रस्तुत करता हूं** कि उपरोक्त परिस्थितियों में, **उक्त** प्रतिष्ठान/उपर्युक्त निदेशक/मालिक ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 **की धारा** 14 (1-ए) और 14 ए के साथ **पठित** पैराग्राफ 4 के तहत अपराध किए हैं, जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रकार **के** प्रावधान अधिनियम, 1952 शिकायत के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित तिथियों को या उसके आसपास। 7. कि मैं आगे प्रस्तुत करता हूँ कि आरोपी नंबर 1 **एम. /एस.** बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल,2. रेव सोलोमन डेविड, प्रबंधक, **बी.यू.एन. आई**, 3. दयाल मसीह, अध्यक्ष, **बी.यू.एन.आई**,4. डेनियल **बुद्ध** मसीह, सचिव-खजांची,5. जॉय एस. सिंह, बी. सी. टी. ए, 6. एस. के. राज, सदस्य **बी.यू.एन.आई.**, संबंधित अवधि के दौरान **थे।**

प्रतिष्ठान प्रोविडेंट फंड इंस्पेक्टर बनाम मेसर्स बैप्टिस्ट सीनियर के प्रभारी थे।

उक्त प्रतिष्ठान के व्यवसाय के संचालन के लिए उत्तरदायी। चूंकि उक्त प्रतिष्ठान/निदेशक/मालिक अपनी उपेक्षा के कारण कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पैरा 4 के साथ पठित अधिनियम की खंड 6 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे हैं, इसलिए उन्होंने अधिनियम की खंड 14 (1-ए) और 14-ए के तहत दंडनीय अपराध किया है।

(4) उपरोक्त शिकायत दर्ज करने के बाद, पक्षों को **बुलाया** गया और आरोप तय करने के लिए मामला तय किया गया।प्रतिवादियों-अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि उत्तर भारत का बैपटिस्ट संघ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है और अभियुक्त व्यक्ति-प्रतिवादी मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्कुलर रोड, भिवानी के कर्मचारियों की पेंशन निधि में योगदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं, क्योंकि भविष्य निधि में योगदान इस स्कूल के प्राचार्य द्वारा किया जाना है। यह भी बताया गया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि आरोपी व्यक्ति संबंधित समय में मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्कुलर रोड, भिवानी के

पदाधिकारी थे और एक विशिष्ट तर्क दिया गया था कि आरोपी/उत्तरदाताओं का स्कूल के मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं था और इनका प्रबंधन प्रिंसिपल द्वारा किया जाता था जिन्हें आरोपी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था।बैपटिस्ट चर्च ट्रस्ट एसोसिएशन संपत्ति का मालिक है और स्कूल नहीं चलाता है।प्रतिद्वंद्वी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"(3) दोनों पक्षों के विद्वान **अधिवक्ताओं** की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और मामले की फाइल को बहुत सावधानीपूर्वक और बारीकी से देखने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि निर्धारण के तहत विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या रिकॉर्ड पर पूर्व-आरोप **पर्याप्त** अभियुक्त व्यक्तियों पर आरोप **करने के लिए पर्याप्त है** या नहीं?शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, **आरोपी व्यक्ति** मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्कुलर रोड, भिवानी के नियोक्ता होने के नाते अधिनियम की खंड 6 के आधार पर अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि में योगदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे, लेकिन वे ऐसा करने में बुरी तरह विफल रहे।उनका यह भी कहना है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि में योगदान नहीं देकर अधिनियम की खंड 14 और 14 ए के तहत दंडनीय अपराध किए हैं।अपना पक्ष साबित **करने** के लिए, शिकायतकर्ता पर यह साबित करना अनिवार्य था कि आरोपी व्यक्ति मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्कुलर रोड, भिवानी में नियोक्ता हैं।वह कानूनी रूप से यह साबित करने के लिए भी बाध्य था कि

अभियुक्त व्यक्तियों का मेसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्कुलर रोड, भिवानी के मामलों पर नियंत्रण था।अधिनियम की खंड 6 के अनुसार, एक नियोक्ता कानूनी रूप से अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि में योगदान करने के लिए बाध्य है।केस फाइल के सावधानीपूर्वक **जांच** से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने यह साबित करने के लिए कोई विशिष्ट सबूत नहीं दिया है कि वे मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्कुलर रोड, भिवानी के नियोक्ता हैं। उन्होंने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं **किया** है कि वे फरवरी 2011 से अप्रैल 2011 तक मेसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल,

सर्कुलर रोड, भिवानी के कर्मचारियों के भविष्य निधि में योगदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त व्यक्तियों का मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्कुलर रोड, भिवानी के मामलों पर नियंत्रण था। उपरोक्त तथ्यों को साबित **करने** के लिए, शिकायतकर्ता को मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्कुलर रोड, भिवानी का रिकॉर्ड तलब करना अनिवार्य था। हालांकि, वह ऐसा करने में बुरी तरह विफल रहे।उपरोक्त तथ्यों से संबंधित साक्ष्य का अभाव में, यह मानने का कोई उचित कारण नहीं है कि आरोपी व्यक्ति मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्कुलर रोड, भिवानी के नियोक्ता थे और वे फरवरी 2011 से अप्रैल 2011 तक स्कूल के कर्मचारियों की भविष्य निधि में योगदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे।यह मानने का कोई उचित कारण नहीं है कि अभियुक्त व्यक्तियों का उपरोक्त अवधि के दौरान मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्कुलर रोड, भिवानी के मामलों पर अंतिम नियंत्रण था। चूंकि शिकायतकर्ता यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि आरोपी व्यक्ति फरवरी 2011 से अप्रैल 2011 तक मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्कुलर रोड, भिवानी के नियोक्ता थे या इस अवधि के दौरान **उनका** मामलों पर उनका नियंत्रण था या वे कानूनी रूप से कर्मचारियों की भविष्य निधि में योगदान करने के लिए बाध्य थे **इसलिए** उन पर अधिनियम की खंड 14 और 14 ए के तहत आरोप नहीं लगाया जा **सकते**। उपरोक्त तथ्यों के अलावा, शिकायतकर्ता ने फरवरी 2011 से अप्रैल 2011 के दौरान मेसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्कुलर रोड, भिवानी के कर्मचारियों के बारे में विशिष्ट साक्ष्य नहीं दिए हैं।उन्होंने विशिष्ट साक्ष्य का नेतृत्व नहीं किया है कि कैसे अभियुक्त व्यक्ति कानूनी रूप से Rs.50,117/- का योगदान करने के लिए बाध्य थे। मान लीजिए, अभियुक्त व्यक्तियों को कभी भी स्कूल के प्राचार्य के रूप में नहीं रखा गया था। हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के अनुसार, **सरकार के निर्देशों के अनुसार** प्राचार्य कानूनी रूप से शिक्षकों और **गैर शिक्षण कर्मचारियों** के वेतन और भत्तों का **समय पर** भुगतान करने के लिए बाध्य है।

प्रोविडेंट फंड इंस्पेक्टर बनाम मैसर्ज बैप्टिरट सीनियर

हालाँकि, शिकायतकर्ता ने वर्तमान शिकायत में प्राचार्य को अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, शिकायतकर्ता के बयान को **ईश्वरीय** सत्य के रूप में नहीं **माना** जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अभिलेख पर **मौजूद साक्ष्य** पूर्व साक्ष्य अभियुक्त व्यक्तियों पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान मामले में, यदि आरोप **पूर्व साक्ष्य अप्रमाणित** है, तो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करना न्यायालय का सर्वोपरि कर्तव्य है ताकि यह देखा जा सके कि क्या यह अभियुक्त के खिलाफ प्रथमदृष्टया **बनता** है या नहीं? यदि प्रथमदृष्टया **कोई** मामला नहीं है या अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त और मजबूत आधार नहीं बनाए गए हैं और आरोप निराधार हैं या कार्यवाही का उद्देश्य मुख्य रूप से किसी अभियुक्त को परेशान करना है, तो न्यायालय के लिए अभियुक्त को आरोपमुक्त करना उचित और उचित है।दूसरे शब्दों में, केवल इस संदेह **के आधार पर आरोप तय नहीं किया** जा सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, बल्कि यह **आरोप तभी तय किया जाना चाहिए जब यह पता चल जाए कि** यह मानने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।"

(5) उसी से आहत होकर, शिकायतकर्ता द्वारा तत्काल याचिका दायर की गई है।

(6) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि ई. पी. एफ. संगठन के भविष्य निधि निरीक्षक सी. डब्ल्यू. 1 के रूप में उपस्थित हुए और दस्तावेजों को प्रदर्शित किया।उक्त गवाह से भी विधिवत जिरह की गई और उसके बल पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी कि **उत्तरदाताओं** पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पी. एफ. कोड सोसायटी के नाम पर नहीं है, बल्कि मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्कुलर रोड, भिवानी के नाम पर है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सी. डब्ल्यू.-1 ने अपनी **जिरह** में स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने आरोपी नंबर 2 के हस्ताक्षर देखे हैं क्योंकि उन्होंने उनके विभाग के साथ **संचार** किया था।इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त व्यक्तियों को स्कूल के मामलों से कोई सरोकार नहीं था। यह जोरदार तर्क दिया गया है कि पेंशन और भविष्य निधि कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं और प्रतिवादी-अभियुक्त को रिहा करने के आदेश के आधार पर, अपराध के अपराधियों को उनके उल्लंघन को बढ़ाने की अनुमति दी गई है।यह भी तर्क दिया जाता है कि आरोप तय करने के चरण में, केवल प्रथमदृष्टया मामला देखा जाना

चाहिए और किसी अन्य सामग्री की जांच नहीं की जा सकती थी। निचली अदालत ने बचाव के समय देखी जाने वाली सामग्री पर भरोसा करते हुए विवादित आदेश पारित किए हैं।

(7) मैंने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरणों पर विचार किया है।

मामले में आगे की कार्यवाही से पहले, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसके उल्लंघन का शिकायत में आरोप लगाया गया हैः-

2. (viii) "पेंशन" का अर्थ है "कर्मचारी पेंशन योजना के तहत देय पेंशन" हैं और इसमें 16 नवंबर, 1995 से प्रभावी कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के शुरू होने से ठीक पहले कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के तहत स्वीकार्य और देय पारिवारिक पेंशन भी शामिल है।

4. अंशदान का भुगतान।-

(1) नियोक्ता अपने द्वारा सीधे या किसी ठेकेदार द्वारा या उसद्वारा से नियोजित कर्मचारी पेंशन कोष के प्रत्येक सदस्य के संबंध में कर्मचारी पेंशन कोष में देय योगदान का भुगतान करेगा।

(2) यह प्रमुख नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने द्वारा सीधे नियोजित कर्मचारियों के संबंध में और ठेकेदार द्वारा या उसद्वारा से नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी पेंशन कोष में देय योगदान का भुगतान स्वयं करे।

[बशर्ते कि केंद्र सरकार विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) के तहत अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के तहत और ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांग वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के तहत कर्मचारी पेंशन कोष में देय

योगदान का भुगतान करेगी, जो कोष की सदस्यता शुरू होने की तारीख से अधिकतम तीन साल तक होगा।

(8) इस के अवलोकन से पता चलेगा कि योगदान देने का आवेदन नियोक्ता के खिलाफ दायर कर दिया गया है। हालाँकि, पेंशन योजना 1995 नियोक्ता को परिभाषित नहीं करती है।जैसा कि उक्त योजना को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की खंड 6 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है, उसी के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे दिया गया हैः-2.ङ) "नियोक्ता" का अर्थ है -

(i) किसी ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में जो एक कारखाना है, कारखाने का मालिक या अधिभोगकर्ता, जिसमें ऐसे मालिक या

अधिभोगकर्ता, मृत स्वामी या अधिभोगकर्ता का कानूनी प्रतिनिधि और, जहां किसी व्यक्ति को कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 7 की उप-धारा (1) के धारा (च) के तहत कारखाने के प्रबंधक के रूप में नामित किया गया है, तो इस प्रकार नामित व्यक्ति; और एजेंट भी शामिल हैं।

((ii) किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, वह व्यक्ति या प्राधिकारी जिसका प्रतिष्ठान के मामलों पर अंतिम नियंत्रण होता है, और जहां उक्त कार्य एक प्रबंधक, प्रबंध निदेशक या प्रबंध एजेंट को सौंपे गए हैं, ऐसे प्रबंधक, प्रबंध निदेशक या प्रबंध एजेंट हैं।

6. योगदान और मामले जिनके लिए योजनाओं में प्रावधान किया जा सकता है।—

नियोक्ता द्वारा कोष में जो दिया जायेगा वह मूल वेतन का 6 (दस प्रतिशत) होगा। किसी भी कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी को उसकी अपनी सेवाओं को बनाए रखने के लिए चाहे वो किसी भी अवधि के

दौरान जिसमें प्रतिष्ठान काम नहीं कर रहा हैं (चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से या ठेकेदार द्वारा या उसद्वारा से नियोजित हो) 7 [महँगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई हो)] **प्रत्येक कर्मचारी को कुछ समय के लिए देना होगा** और कर्मचारियों का योगदान उसके संबंध में नियोक्ता द्वारा देय अंशदान के बराबर होगा और 9 [यदि कोई कर्मचारी ऐसा चाहता है, तो वह राशि 6 [दस प्रतिशत से अधिक हो सकती है।]उसकी मूल मजदूरी, महँगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई हो) **का दस प्रतिशत** इस शर्त के अधीन रहते हुए कि नियोक्ता इस धारा के तहत देय अपने योगदान के **अधिक और** किसी भी योगदान का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा]:

[बशर्ते कि किसी भी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग के लिए अपने आवेदन में, जिसे केंद्र सरकार, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, यह **धारा 6 साक्ष्यों के लिए** इस संशोधन के अधीन होगी [दस प्रतिशत], दोनों स्थानों पर जहां वे पाए जाते हैं, शब्द 10 [बारह प्रतिशत।]प्रतिस्थापित किया जाएगाः]बशर्ते कि जहां इस अधिनियम के तहत देय किसी भी योगदान की राशि में एक रुपये का एक अंश शामिल है, वहां योजना ऐसे अंश को निकटतम रुपये, एक रुपये का आधा या एक रुपये का चौथाई के बराबर **भाग में** करने का प्रावधान कर सकती है।

[स्पष्टीकरण 1]।—इस धारा 12 के प्रयोजनों के लिए, महँगाई भत्ते में कर्मचारी को दी गई किसी भी खाद्य रियायत का नकद मूल्य भी शामिल माना जाएगा।13

[स्पष्टीकरण 2]।—इस 12 [धारा] के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिधारण भत्ता" का अर्थ है **उस** अवधि के लिए देय भत्ता **किसी भी कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी को किसी भी अवधि के दौरान जिसमें प्रतिष्ठान काम नहीं कर रहा है, को अपनी सेवाओं को बनाए रखने के लिए उस अवधि के लिए दिय भत्ता।**

14.(1-ए) एक नियोक्ता जो खंड 6 या खंड 17 की उप-खंड (3) के खंड (ए) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, या अनुपालन करने में चूक करता है, जहां तक यह निरीक्षण शुल्क के भुगतान से संबंधित है, या योजना के **अनुच्छेद** 38 जहां तक यह प्रशासनिक शुल्क के भुगतान से संबंधित है, वह कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि 6 [तीन साल] तक हो सकती है, लेकिन -

(क) जो कर्मचारियों के अंशदान के भुगतान में चूक के मामले में 7 [एक वर्ष और दस हजार रुपये के जुर्माने] से कम नहीं होगा, जिसे नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काट लिया गया है;

(ख) **जो किसी भी अन्य मामले मे** छह महीने से कम नहीं होगा और किसी अन्य मामले में पांच हजार रुपये का जुर्माना होगा;]

बशर्ते कि न्यायालय, निर्णय में दर्ज किए जाने वाले किसी भी पर्याप्त और विशेष कारणों **से**, कम अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकता है।

14-ए. कंपनियों द्वारा अपराध।—(1) यदि इस अधिनियम 4 [, योजना या 5 [पेंशन] योजना या बीमा योजना] के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके लिए जिम्मेदार था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा **और साथ ही कम्पनी को दोषी माना जायेगा** और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगाः

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित **कोई भी बात किसी भी** व्यक्ति को किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा, यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को करने से रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम 4 [, योजना या 5 [[पेंशन] योजना या बीमा योजना] के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि **यह** अपराध किसी निदेशक या **निदेशक** की सहमति या

मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

प्रोविडेंट फंड इंस्पेक्टर बनाम एम/एस बैप्टिस्ट सीनियर

625

माध्यमिक विद्यालय (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

कंपनी के प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण।—इस धारा के चार उद्देश्यों के लिए – **इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए** "कंपनी "**का अर्थ है** कोई भी निगमित निकाय है और इसमें एक फर्म और व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और)

((ii) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ है फर्म में भागीदार।"

(9) उक्त प्रावधान के एक संयुक्त पठन से पता चलता है कि योगदान का भुगतान करने का दायित्व एक नियोक्ता का है और अधिनियम के अधिदेश के भंग के कारण अभियोजन पक्ष को शिकायतकर्ता द्वारा यह अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना चाहता है वह उक्त प्रावधानों के अर्थ के भीतर नियोक्ता है ।

(10) शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि **यह** मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ भी यही मामला दर्ज किया गया था और **उत्तरदाताओं के बैपटिस्ट यूनियर जो उत्तरी भारत के** पदाधिकारी और प्रबंधक होने का दावा **करते** है, उन पर मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है।चूंकि शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि जिस व्यक्ति पर मुकदमा **चलाये जाने की मांग की गई है,** वह मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्कुलर रोड, भिवानी के प्रभारी और संचालन के लिए जिम्मेदार है, इसलिए शिकायतकर्ता पर यह स्थापित करने का बोझ है कि प्रतिवादी मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्कुलर रोड, भिवानी में नियोक्ता हैं।हालाँकि, प्रथमदृष्टया यह स्थापित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में कोई सामग्री नहीं लाई गई थी कि प्रतिवादी नियोक्ता हैं और इस प्रकार, मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कर्मचारियों के भविष्य निधि में योगदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे।

संभावनाओं की अधिकता के आधार पर आपराधिक दायित्व का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।शिकायतकर्ता पर प्रथमदृष्टया यह स्थापित करने का भार है कि प्रतिवादी मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नियोक्ता थे।

(11) 'नियोक्ता' की परिभाषा स्पष्ट रूप से यह स्थापित करती है कि किसी प्रतिष्ठान में, वह प्राधिकारी जिसका मामलों पर अंतिम नियंत्रण होता है और जहां ऐसे मामले प्रबंधक आदि को सौंपे जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नियोक्ता माना जाता है।इसलिए, यह शिकायतकर्ता को यह स्थापित करना और साबित करना है कि जिस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना चाहता है, वह वास्तव में वही है जिसका प्रतिष्ठान के मामलों पर अंतिम नियंत्रण है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस तरह के दायित्व को केवल शिकायतकर्ता के हल्के फुल्के ब्यान या दावे से खारिज कर दिया गया है।

कोई शिकायत जब वैधानिक अनुपालन को सौंपने के लिए शिकायत दर्ज की जाती है तो प्रथमदृष्टया मामले की आवश्यकता के लिए निराधार दावे से कुछ अधिक की आवश्यकता होगी।

(12) यह भी स्पष्ट है कि इस बात का कोई कारण नहीं दिया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा स्कूल या उत्तर भारत के बैपटिस्ट यूनियन से संबंधित रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश किया गया है।यह भी देखा गया है कि निचली अदालत ने विशेष रूप से एक निष्कर्ष दर्ज किया था कि कोई भी आरोपी व्यक्ति कभी भी स्कूल के प्राचार्य के रूप में नहीं रहा और यह भी कहा कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, 2003 के अनुसार, स्कूल के प्राचार्य कानूनी रूप से शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का समय पर और सरकार के निर्देशों के अनुसार भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।इस प्रकार उसे प्रावधानों के तहत एक नियोक्ता माना जाता है क्योंकि इसे कुछ कार्यों को करने के लिए अधिनियम के तहत नामित या अधिकृत किया गया है।हालाँकि, सबसे अधिक ज्ञात कारणों से, स्कूल को प्राचार्य द्वारा से तैयार नहीं किया गया है।अभिलेख पर ऐसी कोई अन्य सामग्री प्रस्तुत नहीं

की गई है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि प्रतिवादी मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नियोक्ता हैं।

पुलिस शिकायत के अलावा किसी अन्य मामले में आरोप तय करने के बारे में कानूनी स्थिति।

(13) बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में

इस न्यायालय द्वारा 2011 के सीआरएम-एम-**11092/2011** में पारित **दिनांक** **28.02.2022** पर निर्णय लिया गया

यह निम्नानुसार आयोजित किया जाता है:6. ..... दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XVII के तहत आरोप निर्धारित किया गया है।चूंकि मामले में विवाद पुलिस रिपोर्ट के अलावा **किसी अन्य** मामले में आरोपमुक्त करने से संबंधित है, इसलिए हम चर्चा को आरोपमुक्त करने के तत्व तक ही सीमित रखेंगे।

7. इसके अलावा, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XVIII की खंड 227 सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे के मामले में आरोपमुक्त करने से संबंधित है और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIX के तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता की खंड 239 मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामले में आरोपमुक्त करने से संबंधित है। इन्हें नीचे दिए गए रूप में निकाला गया है:'227. निर्वहन। यदि, मामले के **रिकार्ड** और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा।'239.

जब अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाएगा। यदि पुलिस रिपोर्ट और **धारा** 173 के तहत **पुलिस रिपोर्ट** उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करने और अभियुक्त की ऐसी जांच करने पर, यदि कोई हो, जिसे मजिस्ट्रेट आवश्यक समझता है और अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के बाद, मजिस्ट्रेट अभियुक्त के खिलाफ

आरोप को निराधार समझता है, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त कर देगा और ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा।

8. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIX की खंड 245 पुलिस रिपोर्ट यानी वर्तमान मामले के तथ्यों के अलावा **अन्य** स्थापित मामलों में आरोपमुक्त करने के मुद्दे से भी **निपटती** है।सी. आर. पी. सी. की खंड 245 इस प्रकार हैः-

245. जब अभियुक्त को आरोपमुक्त **कर दिया** जाएगा।

(1) यदि, **धारा** 244 में निर्दिष्ट सभी साक्ष्यों को लेने के बाद, मजिस्ट्रेट, दर्ज किए जाने वाले कारणों **पर विचार करता है**, यह मानता है कि अभियुक्त के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है जो, यदि निर्विवाद रूप से, उसकी दोषसिद्धि की गारंटी देता है, तो मजिस्ट्रेट उसे आरोपमुक्त कर देगा।

(2) इस **धारा में** कोई भी बात मजिस्ट्रेट को मामले के किसी भी पिछले चरण में आरोपी को आरोपमुक्त करने से रोकने वाली नहीं मानी जाएगी**,** यदि ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से आरोप को आधारहीन मानता है।

9. इसके अलावा, नियम 18 के तहत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नियम और आदेशों का खंड 3, अध्याय I भाग D अन्य वारंट मामलों के मुकदमे में **सुनवाई में** एक आरोपी को आरोपमुक्त करने से संबंधित है।वही इस प्रकार पढ़ता हैः-

18. अभियुक्त **को बरी करना-** साक्ष्य लेने और अभियुक्त की ऐसी जाँच करने के बाद **जैसा कि वह** आवश्यक **समझे**, यदि कोई **ऐसा** मामला नहीं बनाया गया है **जिसका खंडन न करने पर दोषसिद्धि भी आवश्यकता है तो** मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को दोषमुक्त **कर देना चाहिए** और ऐसा करने के लिए उसके कारणों को दर्ज करना चाहिए।हालाँकि, यदि मामले के किसी भी पिछले चरण में मजिस्ट्रेट आरोप को निराधार मानता है, तो वह उस राय के लिए अपने **रिकार्ड** दर्ज कर सकता है और आरोपी को आरोपमुक्त कर सकता है।

10. उसी के अवलोकन से पता चलेगा कि उक्त **धारा** में उपयोग की गई भाषा अलग है जबकि *धारा 227* सीआरपीसी लागू होती है यदि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है*; धारा 239* सीआरपीसी *यह बताती है* जब मजिस्ट्रेट इस *पर विचार करता है* **तो इसे निराधार मानता है।**

आधारहीन बनो '। दूसरी ओर, खंड 245 सी. आर. पी. सी. और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के **नियमों और** और आदेश **के नियम** पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य मामलों **के संबंध** में लागू होते हैं। विधायिका ने वाक्यांश के उपयोग को प्राथमिकता दी है "कोई मामला नहीं **बनता है जिसका यदि खंडन नहीं किया गया तो दोषी ठहराया जाएगा,** यदि अप्रमाणित हो तो दोषसिद्धि की गारंटी देगा।"यह इंगित करना उचित होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 204 के तहत अध्याय XVI के अनुसार प्रक्रिया जारी करने के उद्देश्यों के लिए, निर्धारित आवश्यकता "आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधारों का अस्तित्व" है। इसलिए, जबकि किसी व्यक्ति को **शिकायत के मामले** आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधारों पर में तलब किया जा सकता है, दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 245 के तहत निर्धारित आवश्यकता अलग और अलग है।संभावित बचाव और/या साक्ष्य के संभावित मूल्य पर विचार किए बिना मामले को तार्किक अंत तक ले जाने के लिए केवल आगे की कार्यवाही की पर्याप्तता को पर्याप्तता के तत्व द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।एक गंजे और अप्रमाणित कथन और अनुमान, संभावना, परिकल्पना और संदेह पर भरोसा करने को आरोप तैयार करने के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अजय कुमार **घोष** के मामले में

घोष बनाम झारखंड राज्य और अन्र, आपराधिक 2009 की अपील No.485 ने 18.03.2009 पर निर्णय लिया, जिसे निम्नानुसार देखा गयाः-

'14.हालांकि, पुलिस रिपोर्ट के अलावा **किसी अन्य तरीके से शुरू किए गए** वारंट ट्रायल में, जब आरोपी खंड 244 (1) Cr.P.C के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को अभियोजन पक्ष को सुनना होता है और ऐसे सभी सबूत लेने होते हैं, **जो भी हो सकते हैं** अभियोजन पक्ष के समर्थन में पेश किए **गए** हैं।इसमें मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष के आवेदन पर खंड 244 (2) Cr.P.C के तहत भी गवाहों को सम्मन देना कर सकता है।यह सब प्रमाण है

आरोप लगाने से पहले सबूत **है। यह सब होने के बाद** इन सबके बाद**,** साक्ष्य लिया जाता है**,** तब मजिस्ट्रेट को खंड **245 (1) Cr.P.C** के तहत विचार करना होता है**,** कि क्या आरोपी के खिलाफ कोई मामला **बनता** है**, जिसे खंडन किए जाने पर उसे दोषी ठहराया जा सकता है,** उसे दोषी ठहराए जाने की गारंटी देता है**,** और यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरोपी के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं **बनता** है**,** तो मजिस्ट्रेट **उसे आरोपमुक्त करने के लिए** आगे बढ़ता है।

दूसरी ओर, यदि वह अभियुक्त के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामले के बारे में संतुष्ट होता है, तो मजिस्ट्रेट खंड 246 (1) Cr.P.C के तहत आरोप तय करेगा। **इसके बाद** शिकायतकर्ता को **पुलिस रिपोर्ट पर बारंट ट्रायल के विपरित** आरोप के समर्थन में साक्ष्य देने का दूसरा अवसर मिलता है, जबकि **वहां केवल एक मौका है** ।

पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्यथा स्थापित वारंट परीक्षण में, शिकायतकर्ता को साक्ष्य देने के दो अवसर मिलते हैं, पहला, आरोप तय होने से पहले और दूसरा, आरोप के बाद। बेशक, खंड 245 (2) Cr.P.C के तहत, एक मजिस्ट्रेट मामले के किसी भी पिछले चरण में आरोपी को आरोप से मुक्त कर सकता है, अगर वह आरोप को निराधार **लगता है।**

16. अब, **सी.आर.पी.सी. की धारा** 245 (1) और 245 (2) में स्पष्ट अंतर है। खंड 245 (1) के तहत, मजिस्ट्रेट को खंड 244 के तहत अभियोजन पक्ष के **द्वारा पेश किए गए**

साक्ष्य का लाभ मिलता है और उसे इस बात पर विचार करना होता है कि क्या यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है, तो आरोपी को दोषी ठहराया जाना चाहिए।यदि साक्ष्य में कोई स्पष्ट आपत्तिजनक सामग्री नहीं है, तो मजिस्ट्रेट खंड 245 (1) Cr.P.C. के तहत आरोपी को आरोपमुक्त करने के लिए आगे बढ़ता है।

17. हालाँकि, खंड 245 (2) Cr.P.C के तहत स्थिति अलग है।वहां, उप-धारा (2) के तहत, मजिस्ट्रेट **के पास** मामले के किसी भी पिछले चरण में, यानी इस तरह के साक्ष्य **पेश होने** से पहले ही आरोपी को आरोपमुक्त करने की शक्ति है।हालांकि, खंड 245 (2) Cr.P.C के तहत **किसी भी** आरोपी को आरोपमुक्त करने के लिए, मजिस्ट्रेट को यह निष्कर्ष निकालना होगा कि आरोप निराधार है। उस स्तर पर साक्ष्य पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि **ऐसा कोई सबूत ही नहीं है** मजिस्ट्रेट यह निर्णय 244 Cr.P.C के तहत आरोपी के पेश होने या अदालत के समक्ष लाए जाने या खंड साक्ष्य पेश किए जाने से पहले ले सकता है। खंड 245 (2) Cr.P.C में **आने** वाले शब्द "मामले के किसी भी पिछले चरण में" स्पष्ट रूप से इस स्थिति को सामने लाते हैं।यह देखना बेहतर होगा कि वह "पिछला चरण" क्या है।

18. पिछला चरण स्पष्ट रूप से खंड 244 (1) Cr.P.C के तहत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य **से पहले होगा** या उससे पहले का कोई भी चरण होगा।इस तरह के चरण खंड 200 Cr.P.C के तहत होंगे। **धारा 204 सी.आर.पी.सी.** खंड 200 के तहत, संज्ञान लेने के बाद, मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता या ऐसे अन्य गवाहों की जांच करता है, जो मौजूद हैं। शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की ऐसी जांच आवश्यक नहीं है, जहां **शिकायत** एक लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में की गई है या जहां एक अदालत ने शिकायत की है या **इसके अलावा** आगे, यदि मजिस्ट्रेट खंड 192 Cr.P.C के तहत किसी अन्य मजिस्ट्रेट को जांच या मुकदमे के लिए मामला सौंप **देता** है। खंड 201 Cr.P.C के तहत, यदि मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेने में सक्षम नहीं है, तो वह शिकायत को उचित अदालत में प्रस्तुत करने के लिए वापस कर देगा या शिकायतकर्ता को **उचित न्यायालय में जाने का** निर्देश देगा।

धारा 202 Cr.P.C. प्रक्रिया जारी करने के स्थगन से संबंधित है।उप-धारा (1) के तहत, वह यह तय करने के उद्देश्य से कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश दे सकता है, जो वह उचित समझे, आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। खंड 202 (1) (ए) Cr.P.C के तहत, मजिस्ट्रेट इस तरह की जांच के लिए ऐसा निर्देश नहीं दे सकता है, जहां वह पाता है कि शिकायत किए गए अपराध की सुनवाई विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा की जा सकती है।खंड 202 (1) (बी) Cr.P.C. के तहत ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है, जहां अदालत द्वारा शिकायत की गई हो।खंड 203 Cr.P.C के तहत, मजिस्ट्रेट, शिकायतकर्ता और गवाहों की शपथ पर बयान दर्ज करने या खंड 202 Cr.P.C के तहत आदेशित जांच या जांच के परिणाम को दर्ज करने के बाद, शिकायत को खारिज कर सकता है यदि उसे लगता है कि कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।दूसरी ओर, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह खंड 204 के तहत प्रक्रिया जारी कर सकता है। वह आरोपी की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी कर सकता है और वारंट-मामले में, वह वारंट जारी कर सकता है, या यदि वह उचित समझता है, तो आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सम्मन जारी कर सकता है।खंड 204 Cr.P.C की उप-धाराएं (2), (3), (4) और (5) हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।वास्तव में यह यहाँ पर धारा245 Cr.P.C के तहत निर्दिष्ट पिछला चरण का उल्लेख किया गया है आम तौर पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि अगला चरण केवल खंड 244 Cr.P.C के तहत वारंट मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी की उपस्थिति है। खंड 244 के तहत, आरोपी की उपस्थिति पर, मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष की सुनवाई करने के लिए आगे बढ़ता है और ऐसे सभी साक्ष्य लेने लेता है, जो अभियोजन पक्ष के समर्थन में पेश किए जा सकते हैं।उस स्तर पर वह अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर किसी भी गवाह को सम्मन जारी कर सकता है।इसके बाद खंड 245 (1) Cr.P.C का चरण आता है, जहां मजिस्ट्रेट खंड 244 (1) Cr.P.C के तहत लिए

गए सभी साक्ष्यों पर विचार करने का कार्य करता है, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है, **यदि उसका खंडन नहीं किया गया, तो आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है** मजिस्ट्रेट उसे आरोपमुक्त करने के लिए आगे बढ़ता है।हालाँकि, खंड 245 (2) Cr.P.C के तहत स्थिति अलग है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है।इसके तहत मजिस्ट्रेट के पास मामले के किसी भी पिछले चरण में आरोपी को आरोपमुक्त करने की शक्ति है।हम पहले ही बता चुके हैं कि पिछला चरण धारा 200

से 204 Cr.P.C तक और खंड 244 Cr.P.C के तहत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने तक **हो सकता है**। इस प्रकार, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को तब भी आरोपमुक्त कर सकता है जब अभियुक्त सम्मन **जारी करना** या वारंट के अनुसरण में उपस्थित होता है और खंड 244 Cr.P.C के तहत साक्ष्य देने से पहले ही आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन करता है।(जोर दिया गया)।

12. उपरोक्त पर विचार करने के बाद, यह भी देखने की आवश्यकता है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नियम और आदेश खंड 3, अध्याय डी नियम 18 इस बात पर विचार करते हुए कि आरोप तैयार किया जाना है या नहीं, साक्ष्य की थोड़ी अधिक मात्रा को अनिवार्य करता है।यही बात इस हद तक आवश्यक है कि साक्ष्य की गुणवत्ता, यदि अप्रमाणित है, तो दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के नियम 18 के तहत उपयोग की जाने वाली भाषा दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 245 में उपयोग की जाने वाली भाषा से इस हद तक भिन्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 245 दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 244 के दौरान दर्ज **किए गए** साक्ष्य की पर्याप्तता को संदर्भित करती है। हालाँकि नियम 18 (ऊपर) के तहत ऐसा कोई भेद शामिल नहीं किया गया है।

13. इसलिए, न्यायालय के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह सुसंगत रूप से उक्त प्रावधानों का निर्माण करे क्योंकि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों में दिखाई देते हैं।

14. इसके अलावा, **क्षेत्राधिकार के दायरे की व्याख्या करते हुए आरोप मुक्ति के चरण में की है**, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत संघ बनाम भारत संघ के मामले में।

प्रफुल्ल कुमार सामल और **अन्य**, 1979 ए. आई. आर. (एस. सी.) 366,

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः- 'इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित अधिकारियों पर विचार निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैंः

(1) कि न्यायाधीश के पास संहिता की खंड 227 के तहत आरोप तैयार करने के प्रश्न पर विचार करते समय यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्य की छान-बीन करने और **तोलने** की निस्संदेह शक्ति है कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं।

(2) जहां न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है, जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, वहां न्यायालय आरोप तैयार करने और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में पूरी तरह से उचित होगा।

(3) प्रथमदृष्टया मामला निर्धारित करने के लिए परीक्षण स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और **सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम का पालन** करना मुश्किल है।

सार्वभौमिक अनुप्रयोग का **नियम नीचे** तथापि, यदि मोटे तौर पर दो विचार समान रूप से संभव हैं और न्यायाधीश **इस बात से संतुष्ट** हो जाता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य कुछ संदेह **पैदा करते हैं** लेकिन **अभियुक्त के खिलाफ संदेह गंभीर नहीं है**, तो वह पूरी तरह से अभियुक्त को दोषमुक्त करने के अपने अधिकार के भीतर होगा।

(4) कि संहिता की खंड 227 के तहत **अपने** अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते **समय** न्यायाधीश, जो वर्तमान संहिता के तहत एक वरिष्ठ और अनुभवी न्यायाधीश है, केवल **एक** डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, **पर विचार करना होगा, मामले का विवरण,** न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों के कुल प्रभाव, मामले में दिखाई देने वाली किसी भी बुनियादी दुर्बलताओं आदि पर विचार करना होगा।लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि न्यायाधीश को मामले के पक्ष और विपक्ष की **गहन** जांच करनी चाहिए और सबूतों को ऐसे तौलना चाहिए जैसे कि वह मुकदमा चला रहा हो।

15 इससे भी आगे**,** सज्जन कुमार बनाम सेंट्रल **जांच ब्यूरो** के मामले में।

2010 (9) एससीसी 368, माननीय

उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

'17) Cr.P.C की धारा **227** और **228** के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग।

संहिता की खंड 227 और 228 के दायरे के बारे में अधिकारियों के विचार करने पर, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:- (i) न्यायाधीश के पास यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं, खंड 227 के तहत आरोप तैयार करने के प्रश्न पर विचार करते हुए साक्ष्य की छान-बीन करने और तौलना करने की निस्संदेह शक्ति है।प्रथमदृष्टया मामला निर्धारित करने के लिए परीक्षण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

(ii) जहां न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, वहां न्यायालय आरोप तैयार करने और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में पूरी तरह से उचित होगा।

(ग) न्यायालय केवल डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, **बल्कि** उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्य **के कुल प्रभाव** और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के कुल प्रभाव, किसी भी बुनियादी **कमजोरियों** आदि पर विचार करना होगा। हालाँकि, इस स्तर पर, मामले के पक्ष और विपक्ष की बारीकी से जांच नहीं की जा सकती है और सबूतों को ऐसे तौला नहीं जा सकता है जैसे कि वह एक मुकदमा चला रहा हो।

(iv) यदि अभिलेख की सामग्री के आधार पर, न्यायालय यह राय बना सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया होगा, तो वह **तय कर** सकता है, हालांकि दोषसिद्धि के लिए निष्कर्ष को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।

v) आरोप तैयार करने के समय, अभिलेख पर **मौजुद** सामग्री के संभावित मूल्य **पर विचार नहीं किया** जा सकता है, लेकिन आरोप तैयार करने से पहले न्यायालय को अभिलेख पर रखी गई सामग्री पर अपने न्यायिक दिमाग को लागू करना चाहिए और **इस बात से** संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा अपराध करना संभव था।

vi) धारा 227 और 228 के स्तर पर, न्यायालय को यह पता लगाने के लिए अभिलेख पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या उनसे उनके अंकित मूल्य पर सामने आने वाले तथ्य कथित अपराध का गठन करने वाले सभी घटकों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं।इस सीमित उद्देश्य के लिए, साक्ष्य की छान-बीन करें क्योंकि उस प्रारंभिक चरण में भी यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अभियोजन पक्ष **द्वारा कही गई सभी बातों को** भी सुसमाचार सत्य के रूप **स्वीकार कर लिया जाए**, भले ही वह सामान्य ज्ञान या मामले की व्यापक संभावनाओं के खिलाफ हो।

vii) यदि दो विचार संभव हैं और उनमें से एक केवल संदेह को जन्म देता है, जैसा कि गंभीर संदेह से अलग है, तो विचारण न्यायाधीश को अभियुक्त को आरोपमुक्त करने का अधिकार होगा और इस स्तर पर, उसे यह देखने का अधिकार नहीं होगा कि परीक्षण दोषमुक्ति में समाप्त होगा या दोषमुक्त **में**।

16. राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय **द्वारा तमिलनाडु राज्य के मामले में**

पुलिस सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक बनाम एन. सुरेश राजन और अन्य, **2014 (11)** एस. सी. सी. **709**

इसके अंतर्गतः- **निम्नानुसार आयोजित**

'19.XXXXXXXXXXX.यह सच है कि आरोपमुक्त करने के लिए आवेदनों पर विचार करते समय, न्यायालय अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है या डाकघर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और यह पता लगाने के लिए साक्ष्य की छान-बीन कर सकता है कि क्या लगाए गए आरोप निराधार हैं या नहीं ताकि आरोपमुक्त करने का आदेश पारित किया जा सके। यह **सामान्य** बात है कि आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में, अदालत को इस धारणा के साथ आगे बढ़ना होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री सही है और उक्त सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे सामने आने वाले तथ्य **सही है।** उनके अंकित मूल्य पर **उभरने से** कथित अपराध का गठन करने वाले सभी तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं।इस स्तर पर,

सामग्री के संभावित मूल्य **पर ध्यान देना** होगा और अदालत से मामले में गहराई से जाने यह मानने की उम्मीद नहीं की जाती है कि सामग्री दोषसिद्धि की गारंटी नहीं देगी। हमारी राय में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने के लिए कोई आधार है कि अपराध किया गया है और न कि क्या आरोपी को दोषी ठहराने के लिए कोई आधार बनाया गया है।इसे अलग तरह से **कहे तो**, यदि अदालत सोचती है कि आरोपी ने अपने संभावित मूल्य पर रिकॉर्ड पर **मौजूद** सामग्री के आधार पर अपराध किया होगा, तो वह आरोप तय कर सकता है; हालांकि दोषसिद्धि के लिए, अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि आरोपी ने अपराध किया है।कानून इस स्तर पर लघु परीक्षण की अनुमति नहीं देता है। इस संबंध में श्योराज सिंह अहलावत और अन्य बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, के मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 52, जिसमें, इस मुद्दे पर विभिन्न

निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद, इस न्यायालय ने ओंकार नाथ मिश्रा बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2008) 2 एस. सी. सी. 561 में लिए गए निम्नलिखित दृष्टिकोण का समर्थन कियाः 561 यह मामूली बात है कि आरोप तय करने के चरण में अदालत को यह पता लगाने के लिए अभिलेख पर **मौजूद** सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है कि क्या वहां से सामने आने वाले तथ्य, उनके अंकित मूल्य पर लिए जाने पर **सामने आए हैं**, कथित अपराध का गठन करने वाले सभी तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं।उस स्तर पर, अदालत से रिकॉर्ड पर सामग्री के संभावित मूल्य में गहराई से जाने की उम्मीद नहीं की जाती है।जिस बात पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या यह मानने के लिए कोई आधार है कि अपराध किया गया है और आरोपी को दोषी ठहराने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है।उस स्तर पर, **यहां तक कि** सामग्री पर स्थापित मजबूत संदेह भी, जो अदालत को कथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यात्मक तत्वों के अस्तित्व के बारे में एक अनुमानित राय बनाने के लिए प्रेरित करता है, उस अपराध के **घटित होने के** संबंध में आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने को उचित ठहराएगा।

17. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय **ने**

संजय कुमार राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और **अन्य के मामले में**

2021 की दाण्डिक अपीलीय No.472, निम्नानुसार देखी गईः-

16. इसके अलावा, यह अच्छी तरह से **स्थापित है कि** आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार करते निचली निचली अदालत केवल डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना है। अदालत को यह आदेश **पता लगाने के लिए** सबूतों की छान-बीन करनी होगी कि क्या संदिग्ध पर मुकदमा चलाने के द्वारा पर्याप्त आधार हैं।न्यायालय को व्यापक संभावनाओं, प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों के कुल प्रभाव और मूल पर विचार करना होगा।

635

प्रोविडेंट फंड इंस्पेक्टर बनाम एम/एस बाप्टिस्ट सीनियर

माध्यमिक विद्यालय (विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

मामले में दिखाई देने वाली दुर्बलताएँ आदि **पर विचार करना होगा**।[भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल, 5 (1979) 3 एससीसी 4]। इसी तरह, **जरूरत पड़ने पर** अदालत के पास आवश्यकता पड़ने पर उचित मामलों में आगे की जांच का आदेश देने का पर्याप्त विवेकाधिकार है।

18. इसके अलावा, इस न्यायालय ने सुरिंदर कुमार उपनाम पालू सिंह और अन्य के मामले में 1982 के आपराधिक संशोधन No.1574, 1982 में पारित **दिनांक** 17.05.1983 पर निर्णय लिया, जिसमें **निम्नानुसार से रखा**-

6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 245 और 246 संहिता के अध्याय XIX-B में पाई जाती हैं। ये पुलिस रिपोर्ट के अलावा **अन्यथा** स्थापित मामलों पर लागू होते हैं। प्रावधानों का एक समान समूह धारा 239 और 243 **जो** पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामलों से संबंधित संहिता के अध्याय XIX-I में पाए जाने वाले है। जहाँ तक सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे का संबंध है, चाहे वह पुलिस रिपोर्ट पर **या शिकायत पर** शुरू किया गया हो या शिकायत, कानून के प्रासंगिक प्रावधान संहिता की धारा 227 और 228 हैं।उपरोक्त दोहरे प्रावधानों के तीन सेटों के चरण के लिए, समान रूप से समझी **जाने वाली** कानूनी स्थिति यह है कि न्यायालय को परीक्षण लागू करना होगा कि क्या **आगे की** कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है और क्या दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार **है या** नहीं है, और जब प्रथमदृष्टया सबूत होता है तो मामले को पेश किया जाना चाहिए, भले ही किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के पास एक प्रशंसनीय बचाव हो। बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह, ए. आई. आर. 1977, 2018 सुप्रीम कोर्ट **के उनके अधिपत्य मे** चंद्र देव सिंह बनाम प्रकाश चंद्र बोस उपनाम चबी बोस और एक अन्य, ए. आई. आर. 1963 सुप्रीम कोर्ट 1430 पर ध्यान **रखते** हुए सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप्स ने निम्नलिखित टिप्पणी की:- **इस प्रकार देखा गया :**

"इन दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, जैसा कि वे होने चाहिए, यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुकदमे की शुरुआत और प्रारंभिक चरण में **अभियोजक द्वारा पेश किए जाने वाले सबूतों की** सच्चाई, सत्यता और प्रभाव का सावधानीपूर्वक निर्णय नहीं किया

जाना चाहिए।न ही अभियुक्त के संभावित बचाव के साथ कोई **महत्व दिया** जाना चाहिए।मुकदमे के उस चरण में न्यायाधीश के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह किसी भी विस्तार से विचार करे और एक संवेदनशील **तराजू में तोले** कि क्या तथ्य, यदि साबित **होने पर सही होंगे**, तो अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होंगे या नहीं।परीक्षण और निर्णय का मानक जो अभियुक्त के दोषी या अन्यथा के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करने से पहले लागू किया जाना है, संहिता की **धारा** 227 या **धारा** 228 के तहत मामले **का निर्णय** करने के चरण में बिल्कुल लागू नहीं किया जाना है।उस स्तर पर न्यायालय को यह नहीं देखना है कि क्या

अभियुक्त के दोषसिद्धि के लिए **पर्याप्त** आधार **है** या क्या मुकदमा उसकी दोषसिद्धि **के साथ** समाप्त होना निश्चित है। यदि मामला संदेह के क्षेत्र में रहता है, अभियुक्त के खिलाफ प्रबल संदेह, मुकदमे के समापन पर उसके अपराध के प्रमाण की जगह नहीं ले सकता है। लेकिन प्रारंभिक चरण में यदि कोई मजबूत संदेह है जो न्यायालय को यह सोचने के लिए **मजबूर** करता है कि यह मानने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो न्यायालय के लिए यह कहना **सम्भव** नहीं है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

लेकिन रमेश सिंह के मामले (ऊपर) में, यह भी नोट किया गया कि निर्मलजीत सिंह हून बनाम बंगाल राज्य और अन्य मामले में, ए. आई. आर. 1972 सुप्रीम कोर्ट 2639 शेलाट, जे. ने स्पष्ट रूप से आगे कहा था, "जब तक कि मजिस्ट्रेट को यह पता नहीं चलता है कि उनके सामने पेश किया गया साक्ष्य यदि वह सबूत प्रथमदृष्टया मामला बनाता है।"आंतरिक रूप से अविश्वसनीय है, तब तक प्रक्रिया से इनकार नहीं किया जा सकता है इनमें से कोई भी मामला दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 245 का नहीं है।

7. लेकिन यह अभिव्यक्ति "**अगर खण्डन नहीं किया गया तो उसे दोषी ठहराया जायेगा**" शायद संहिता की **धारा** 245 की उचित व्याख्या की दिशा में एक संकेत है। इस तरह की अभिव्यक्ति **का प्रयोग संहिता की धारा** 239/240 या **धारा** 227/228 में नियोजित नहीं किया गया है।यहाँ, शिकायतकर्ता **के** गवाहों से जिरह करके **स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के सबूतों को स्वाभाविक रूप से** खंडन करने के लिए **सामग्री लाई जा सकती है** और इस तरह यह दावा किया जा सकता है कि यह "स्व-विरोधाभासी या आंतरिक रूप से अविश्वसनीय" हो गया है **जैसा कि** यह अभिव्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चंद्र देव सिंह के मामले (ऊपर) में प्रयोग की गई थी। उस स्तर पर, मेरे विचार से, न्यायालय को यह देखने का अधिकार है कि अभियोजन मामले में अंतर्निहित कमजोरियाँ, बुनियादी दुर्बलताएँ और असंभवताएँ हैं **या नहीं** लेकिन, उस निष्कर्ष पर पहुंचने **के लिए** ट्रायल मजिस्ट्रेट को निश्चित रूप से उद्देश्य के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है।संहिता की खंड 245 की उप-खंड (2) में भी, मजिस्ट्रेट मामले के किसी भी पिछले चरण में आरोपी को आरोप से मुक्त कर सकता है यदि वह आरोप को निराधार मानता है।इसलिए, मेरे विचार में, संहिता की खंड 245 के स्तर पर भी, मजिस्ट्रेट गवाहों की **जिरह** के दौरान पेश की गई सामग्री को ध्यान में रख सकते हैं और यदि **कोई विस्वश्नीय** बचाव पेश किया गया है, तो मामले को पूरी तरह से तौलें और कहें कि अभियोजन मामला आंतरिक रूप से अविश्वसनीय है और दुर्बलताओं और असंभवताओं से ग्रस्त है।

9. अनिल कपूर बनाम वित्त-सह-स्वास्थ्य सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन, 1973 चंडीगढ़ लॉ री-पोर्टर 601 में, एक माननीय एकल न्यायाधीश ने महंत एबी दास (उपरोक्त) को लागू करते हुए कहा कि **चार्ज के स्तर पर केवल** प्रथमदृष्टया मामले को देखा जाना चाहिए। एक प्रथमदृष्टया मामले का अर्थ है प्रथमदृष्टया साक्ष्य द्वारा स्थापित एक मामला, जिसका अर्थ है, "**तथ्य का अनुमान लगाने** या प्रश्न में तथ्य को स्थापित करने के

लिए कानून में पर्याप्त सबूत, जब तक कि **इसका** खंडन न किया जाए।"अब, यहाँ फिर से, "कानून में पर्याप्त सबूत" का अर्थ होगा, जैसा कि मैं समझता हूँ, **मजिस्ट्रेट के सामने** सबूत की स्थिति **सुझावों के साथ परस्पर जुई हुई और उलझी हुई थी** उस स्तर पर, यह कहना कि उन्हें उनकी अनदेखी करनी चाहिए और अभियोजन पक्ष के मामले को मूल रूप से शुद्ध और बेदाग रखना चाहिए, संहिता की **धारा** 245 की भाषा में हिंसा का कारण बनता है।निश्चित रूप से, उस स्तर पर उसे केवल अभियोजन पक्ष के मामले को ही नहीं देखना है, और बचाव पक्ष के मामले को बाद के चरण में देखना टालना है, बल्कि जैसा कि मुझे लगता है, यह निर्धारित करने के लिए कि अभियोजन पक्ष का मामला आंतरिक रूप से भरोसेमंद है या नहीं, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड पर उपलब्ध पूरे **साक्ष्यों** को देखना **होगा**। यदि ऐसा है, तो उसे एक आरोप तय करना चाहिए और यदि ऐसा नहीं है, तो उसे आरोप तय करने के लिए अनुष्ठानिक रूप से आगे बढ़ने और फिर अंत में निर्णय देने की आवश्यकता का कोई मतलब नहीं है कि अभियोजन पक्ष का मामला आंतरिक रूप से ऐसा **ही** है। मुझे लगता है कि यह अदालत के बहुमूल्य समय की बर्बादी और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।मैं इसे इस तरह **ही** रखता हूँ।

19. इसके अलावा, यह न्यायालय सुभाष चंदर बनाम पंजाब राज्य के मामले में आपराधिक विविध मामले में पारित हुआ।1996 का No.3240-M, यह निम्नानुसार देखा गया था:-

(8) संहिता की **धारा** 245 के अवलोकन से, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, यह स्पष्ट है कि आरोप तैयार करने से पहले, अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करना और यह देखना कि क्या यह अभियुक्त के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला **बनता** है, न्यायालय का **सर्वोपरि** कर्तव्य है।संहिता की खंड 245 का दायरा साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बारे में नहीं कहता है, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके द्वारा लगाए गए आरोपों के प्रति ईमानदारी और ईमानदारी से विचार करने को अनिवार्य करता है और यह कि न्यायालय यह पता लगाएगा कि किसी कथित अपराध के आधार या **सामग्री क्या** हैं।यह खंड एक यांत्रिक दृष्टिकोण पर विचार नहीं करता है,

बल्कि यह **प्रथम दृष्टया मामले लेकर आधार और स्थापना** के अस्तित्व को जानने के लिए एक उचित और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की अपेक्षा करता है।

यदि कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं है, या अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त और मजबूत आधार नहीं बनाए गए हैं और आरोप निराधार हैं या कार्यवाही का उद्देश्य मुख्य रूप से किसी अभियुक्त को परेशान करना है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय के लिए अभियुक्त को आरोपमुक्त करना उचित और उचित है और इस प्रकार न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सकता है।सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाममहाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 545:यह आयोजित किया गया था:

यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोप तय करने के चरण में न्यायालय को इस बात पर विचार करने के लिए अपने न्यायिक दिमाग **का उपयोग** नहीं करना है कि क्या अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने का अनुमान लगाने के लिए कोई आधार है या नहीं।आरोप तय करने का आदेश व्यक्ति की स्वतंत्रता को काफी हद तक प्रभावित करता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय स्वचालित रूप से केवल इसलिए आरोप तय करता है क्योंकि अभियोजन अधिकारी खंड 173 में निर्दिष्ट दस्तावेजों पर भरोसा करके मामले को स्थापित करना उचित समझते हैं।आरोप तय करने की जिम्मेदारी न्यायालय की है और ऐसा करने के सवाल पर न्यायिक रूप से विचार करना पड़ता है।अभिलेख पर सामग्री को पूरी तरह से स्वीकार किए बिना **इसे** अभियोजन पक्ष के निर्णय को आंख मूंदकर नहीं अपनाना चाहिए।"

20. **इस** के अवलोकन से पता चलता है कि न्यायालय से डाकघर के रूप में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती है और न्यायाधीश को साक्ष्य के साथ-साथ उसके सामने रखी गई सामग्री को भी जांचना और तौलना पड़ता है।इसलिए, भले ही न्यायालय आरोप/आरोपमुक्त करने के चरण में साक्ष्य के संभाव्य मूल्य **पर विचार ना करे**, यदि दो विचार हैं जो संभव हैं और उनमें से केवल एक संदेह को जन्म देता है, तो न्यायाधीश को अभियुक्त को आरोपमुक्त करने का अधिकार होगा।कानून न्यायालय को साक्ष्य के संभावित मूल्य में गए बिना इसकी जांच करने और यह निर्धारित करने की अनुमति देगा

कि क्या यह, यदि इसका खंडन नहीं किया जाता है, तो प्रथमदृष्टया दोषसिद्धि का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।"

(14) यह नहीं माना जा सकता है कि आरोप हमेशा केवल इसलिए तय किया जाना चाहिए क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में आरोप लगाया गया है।प्रथमदृष्टया साक्ष्य की आवश्यकता को केवल मौखिक गवाही से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है।प्रथमदृष्टया आवश्यकता के लिए ऐसे कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के अस्तित्व की आवश्यकता होगी जो आरोपी के केवल संदिग्ध होने के बजाय आरोपी के खिलाफ एक धारणा को जन्म देगा।इस तरह की धारणा को अप्रमाणित और अप्रमाणित गंजे दावों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब

एक वैधानिक प्राधिकरण परिभाषित या निर्धारित है और अभियोजन दस्तावेजी साक्ष्य और वैधानिक दायित्व के उल्लंघन पर आधारित है।इसका पालन नहीं किया जा सकता है कि पीड़ा के पास यह निर्धारित करने का कोई साधन नहीं था कि कौन जिम्मेदार है और मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है और अभियोजन एजेंसी की ओर से इस तरह के दायित्व से उसे सभी और विभिन्न प्रकार के लोगें पर मुकद्मा चलाने का दायित्व मिलना चाहिए।किसी न्यायिक संस्था और उसके पदाधिकारियों से संबंधित तथ्य का बयान ऐसा तथ्य नहीं है जिसे अनुमानित किया जा सके।इसे प्रथमदृष्टया कुछ सामग्री द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए।न्यायालय, आरोप तय करने के चरण में, उक्त साक्ष्य के संभावित में नहीं जाएगा, हालांकि, किसी भी साक्ष्य की अनुपस्थिति में को खारिज या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। किसी शिकायतकर्ता को इस हद तक कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है कि उसके द्वारा नामित सभी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इसके बावजूद कि मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी न्यायिक संस्था से संबंधित कोई सामग्री की अनुपस्थिति में यदि इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो शिकायतकर्ता को किसी भी संख्या में अभियुक्तों को शामिल करने मुकद्मा

चलाने की मांग करने वाले उस प्रतिष्ठान का संबंध उनके अभियोजन का दावा करने का बेलगाम अधिकार होगा,

(15) यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि आपराधिक अभियोजन का किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है और इस तरह की स्वतंत्रता को शिकायतकर्ता की इच्छा पर कम नहीं किया जा सकता है।एक बार जब कोई शिकायतकर्ता किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का विकल्प चुनता है, तो प्रथमदृष्टया उस पर यह स्थापित करने का बोझ पड़ता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किसी न्यायिक संस्था को चूक के कृत्यों के लिए मुकदमा चलाने के लिए चुना गया व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जो प्रबंधन और न्यायिक संस्था के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं और अंतिम नियंत्रण में हैं न्यायिक ईकाई और प्रबंधन और मामलों पर मुकद्मा चलाने की मांग की गई है हालाँकि, याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता यह स्थापित करने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है कि कैसे उत्तरदाता-अभियुक्त का मैसर्स बैपटिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मामलों पर अंतिम नियंत्रण रखते हैं।जब तक उत्तर भारत के बैपटिस्ट संघ को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अर्थ के भीतर एक 'नियोक्ता' नहीं माना जाता है, तब तक उत्तर भारत के बैपटिस्ट संघ के पदाधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, 2003 के अर्थ में 'नियोक्ता' उस स्कूल का प्राचार्य होता है जिसे आरोपी के रूप में भी नहीं रखा गया है।परिसर का मालिक उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का नियोक्ता नहीं होगा। शिकायतकर्ता द्वारा यह स्थापित किया जाना चाहिए कि परिसर का मालिक उस प्रतिष्ठान के मामलों को भी नियंत्रित करता है जिसके खिलाफ चूक का आरोप लगाया गया है।उक्त भार को मुख्य रूप से शिकायतकर्ता द्वारा निर्वहन किया जाना है जो प्रतिवादी पर मुकदमा चला रहा है और केवल तभी जब पर्याप्त सामग्री है

इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है वह प्रतिष्ठान के मामलों का प्रभारी है, तो क्या इसका बोझ उस व्यक्ति

पर पड़ेगा जिस पर मुकदमा **चलाने की मांग की गई है**। यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के मामले में उपरोक्त कमियों को देखा और इसलिए, खंड 245 Cr.P.C के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग प्रतिवादी को आरोपमुक्त करने के लिए किया। **मुझे लगता है कि** विवादित आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है और यह रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की किसी भी गैर-प्रशंसा से भी पीड़ित नहीं है।

(16) तदनुसार याचिका खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक : पूनम